>

Title: Need to address the problem of annual flood and drought situation in Bihar.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): बिहार की कुल आबादी का 76 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है और इसमें एक-तिहाई से ज्यादा भाग खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करता है। परंतु सदन को बताते हुए खेद हो रहा है कि बिहार का एक हिस्सा हर साल बाढ़ की चपेट में रहता है और दूसरा हिस्सा सूखे की चपेट में। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में बाढ़ एवं सुखाड़ की समस्या का समाधान करने हेतु जो स्थायी उपाय किए जाने हैं वह अभी तक नहीं किए गए हैं। आजादी के 67 वर्ष बाद भी इस समस्या के निदान के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। इस वर्ष 15 अगस्त तक बिहार में 27 प्रतिशत से कम बारिश हुई है। नवादा एवं सीतामढ़ी में तो 72 प्रतिशत सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं गया, वैशाली, लखीसराय, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, समस्तीपुर, जहानाबाद आदि में 50 से लेकर 68 प्रतिशत तक सामान्य से कम वर्षा के कारण स्थिति भयावह हो गई है। परंतु अभी तक राज्य के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है जबकि वर्ष 2010 में 21 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी जिसमें राज्य के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर उत्तरी बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं जिसमें करोड़ों रूपये की फसल को नुकसान पहुँचता है। कई लोगों की जानें चली जाती है और सैकड़ों पशुओं की मौत हो जाती है। इस साल पटना, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा एवं गोपालगंज जिलों के कुल 43 प्रखंडों के 2152 गाँव के 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। बाढ़ से बचने के लिए कोसी क्षेत्र में हाई लेवल डैम, कमला के ऊपर चीसापानी में हाई लेवल डैम व बागमती के ऊपर नूनथर में हाई लेवल डैम निर्माण हेतु सरकार द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है। सोन नहर की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि का इस कार्य में अभी तक उपयोग नहीं किया गया है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि बिहार में सुखाड़ एवं बाढ़ की समस्या जो हर साल आती है उसका स्थायी समाधान किया जाए जिससे लोगों के जान-माल की रक्षा के साथ-साथ देश में खाद्यान्न एवं सब्जियों का उत्पादन को बढ़ाया जा सके।